E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
Impact Factor: 6.49
https://multiresearchjournal.theviews.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 3; Issue 4; 2025; Page No. 40-44

Special Issue of International Seminar (10 December 2025)
On the Topic
Human Rights and Education
By
Faculty of Education, Faculty of Arts and Social Sciences, IASE (DU), Sardarshahar, Churu, Rajasthan - 331403

मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

[1]डॉ. आरती कोरी एवं [2]नेहा सिंह

[1]प्रोफेसर, गृह विज्ञान, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत
[2]शोधार्थी, गृह विज्ञान, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21426823

Corresponding Author: डॉ. आरती कोरी

Abstract
प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), जननी सुरक्षा योजना (JSY), पोषण अभियान तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी अनेक योजनाएँ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा समग्र विकास को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं, किन्तु इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रशासनिक कमियाँ, संसाधनों का अभाव, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, सेवाओं की अनियमित उपलब्धता, सामाजिक एवं आर्थिक बाधाएँ, जागरूकता का अभाव तथा भौगोलिक कठिनाइयाँ जैसी समस्याएँ उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के करनैलगंज एवं परसपुर विकास खण्डों के 10 ग्रामों से उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण द्वारा चयनित 400 ग्रामीण महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आँकड़े संकलित किए गए। अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के मध्य संबंध का विश्लेषण काई-वर्ग (χ^2) परीक्षण द्वारा किया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार जिन क्षेत्रों में क्रियान्वयन संबंधी समस्याएँ कम थीं वहाँ कार्यक्रम अधिक प्रभावी पाए गए, जबकि अधिक समस्याओं वाले क्षेत्रों में प्रभावशीलता में उल्लेखनीय कमी देखी गई। सांख्यिकीय विश्लेषण में $\chi^2 = 58.19$ (df = 2, p = 0.000) प्राप्त हुआ, जिससे स्पष्ट हुआ कि क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध विद्यमान है, अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गई। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, प्रभावी प्रशासनिक समन्वय, नियमित निगरानी, प्रशिक्षित कार्यबल, समय पर सेवा वितरण तथा लाभार्थियों में जागरूकता बढ़ाकर कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी, आशा एवं एएनएम कार्यकर्ताओं तथा भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान करता है तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण एवं सतत सामाजिक विकास को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है।

Keywords: मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रम, क्रियान्वयन, समस्याएँ एवं बाधाएँ, कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, आईसीडीएस, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, ग्रामीण महिलाएँ इत्यादि।

Introduction
भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जहाँ माताओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण तथा समग्र विकास राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। किसी भी देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति उसके नागरिकों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य स्तर पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा छह वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, सुरक्षित मातृत्व, प्रसव पूर्व

एवं प्रसवोत्तर देखभाल तथा समुचित परामर्श उपलब्ध कराना है। समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, मिशन शक्ति तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, कुपोषण को नियंत्रित करना, एनीमिया की समस्या का समाधान करना, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना तथा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना है।

यद्यपि सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, फिर भी इन योजनाओं के अपेक्षित परिणाम सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्राप्त नहीं हो सके हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान अनेक प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा व्यवहारगत समस्याएँ सामने आती हैं, जो इनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। कई स्थानों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का अपर्याप्त संचालन, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, पोषाहार की अनियमित आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली की कमजोरी, विभागीय समन्वय की कमी तथा लाभार्थियों तक समय पर सेवाएँ न पहुँच पाना प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं में योजनाओं के प्रति सीमित जागरूकता, अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ, लैंगिक असमानता, परिवार के निर्णयों में महिलाओं की सीमित भागीदारी, आर्थिक अभाव तथा स्वास्थ्य संबंधी मिथक भी इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली इन समस्याओं का सीधा प्रभाव मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ, पोषाहार, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियाँ, पोषण परामर्श तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं, तब कार्यक्रमों के मूल उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते। परिणामस्वरूप कुपोषण, एनीमिया, कम वजन वाले बच्चों का जन्म, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, संक्रमण तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ अपेक्षित स्तर पर कम नहीं हो पातीं। इससे सरकारी संसाधनों के उपयोग की दक्षता भी प्रभावित होती है तथा योजनाओं के प्रति समुदाय का विश्वास कम होने की संभावना बढ़ जाती है।वर्तमान समय में यह आवश्यक हो गया है कि केवल योजनाओं के अस्तित्व अथवा लाभार्थियों की संख्या का अध्ययन ही न किया जाए, बल्कि उनके वास्तविक क्रियान्वयन की गुणवत्ता, सेवा वितरण प्रणाली, लाभार्थियों की पहुँच, कार्यकर्ताओं की भूमिका, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा कार्यक्रमों के समक्ष उपस्थित बाधाओं का भी गहन विश्लेषण किया जाए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-से कारक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहे हैं तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा एवं एएनएम कर्मियों तथा स्थानीय समुदाय को कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रदान करेगा।

अतः "मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन" अत्यंत प्रासंगिक एवं समसामयिक शोध विषय है। यह अध्ययन न केवल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यमान चुनौतियों की पहचान करेगा, बल्कि उनके कारणों का विश्लेषण करते हुए कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने, सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में स्थायी सुधार हेतु उपयोगी निष्कर्ष एवं व्यावहारिक सुझाव भी प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार यह अध्ययन मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन तथा सतत् सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व- भारत सरकार द्वारा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार तथा महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान तथा विभिन्न टीकाकरण एवं पोषण संबंधी योजनाएँ। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ, संतुलित पोषण, सुरक्षित प्रसव तथा बच्चों के समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है। तथापि, इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जागरूकता का अभाव, संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव, प्रशासनिक शिथिलता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ़ियाँ, भौगोलिक कठिनाइयाँ तथा लाभार्थियों तक सेवाओं की सीमित पहुँच जैसी अनेक समस्याएँ एवं बाधाएँ विद्यमान हैं, जिनके कारण योजनाओं के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली वास्तविक समस्याओं एवं बाधाओं की पहचान कर उनके कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जा सके। यह अध्ययन न केवल योजनाओं की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों एवं कमियों का मूल्यांकन करने में सहायक होगा, बल्कि नीति-निर्माताओं, प्रशासकों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक सुझाव भी प्रदान करेगा। साथ ही, अध्ययन के निष्कर्ष मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण स्तर, सेवा-प्राप्ति तथा लाभार्थियों की संतुष्टि में सुधार लाने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रकार यह अध्ययन मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता, पहुँच एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ महिलाओं एवं बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

सम्बंधित साहित्य- सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है।

सेनगुप्ता, वी० (2012) [1]**:** ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं को जागरूक करनाः एक समाजशास्त्रीय अनुशीलन (जिला: जाँजगीर-चाम्पा के नवागढ़ ब्लाक के संदर्भ में) शोध अध्ययन किया। शोध के उद्देश्य-महिला एवं बाल विकास विभाग का उद्देश्य निम्न स्तरीय जीवन यापन कर रहे महिलाओं एवं बच्चों का जीवन स्तर सुधारना है तथा विभिन्न स्तर की योजनाओं का संचालन करना।इसका भी पता लगाना कि सम्बंधित योजनाओं का लाभ महिलाओं एवं बच्चों को मिलता है अथवा नहीं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है।कार्यक्रमों से धीरे-धीरे उनके आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक, साँस्कृतिक आदि सभी दृष्टि से विकास हो रहा है।शोध प्रविधि-महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं मिलने वाली लाभ के प्रति महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा प्राथमिक सूचनाएँ एकत्र की गई। अध्ययन हेतु 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।निष्कर्ष- महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थिति के अंतर्गत प्राचीन काल में महिलाओं की अत्यन्त ही निम्न

थी, जब स्त्रियों की स्थिति ही ठीक नहीं थी, तब उनके संतानों की स्थिति ठीक कैसे हो सकती थी। समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी। नारियों के पालन-पोषण को पड़ोसी के पौधों के समान बताया जाता है।

सुरवाडे जितेंद्र बी एट अल. (2013) [2]: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंक 3। लातूर जिले में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आईसीडीएस प्रणाली के उपयोग का आकलन करने के लिए एक क्रॉस-सेक्शनल शोध किया गया। 500 बच्चों को भर्ती किया गया, जिनमें से 250 शहरी क्षेत्रों से और 250 ग्रामीण क्षेत्रों से थे। प्रत्येक क्षेत्र में 250 बच्चों को शामिल करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया। ग्रामीण ब्लॉक में कुल 254 बच्चे और शहरी ब्लॉक में 252 बच्चे नामांकित किए गए। शहरी क्षेत्रों में, 48.03% बच्चों ने पूरक पोषण सेवाओं का संतोषजनक ढंग से उपयोग किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल 37.7% बच्चों ने इस सेवा का लाभ उठाया। अनौपचारिक पूर्व-शिक्षा सेवाओं का उपयोग शहरी क्षेत्रों में 57.72% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 53.79% की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से किया गया। स्वास्थ्य जांच सुविधाओं का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में 25% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक था।
ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सेवाओं का उपयोग 21.65% था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सेवाओं का उपयोग क्रमशः 90.95% और 94.44% था। कुपोषित बच्चों की व्यापकता शहरी क्षेत्रों में 46.46% और ग्रामीण क्षेत्रों में 55.56% थी। कुपोषण की व्यापकता 50.99% थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों का अनुपात 55.56% था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 46.46% था।
थनेश (2014) [3] ने इस निष्कर्ष का समर्थन करते हुए बताया कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों को अनियमित उपस्थिति और शैक्षणिक संसाधनों की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ कमजोर रहती हैं। इसी प्रकार, शर्मा एवं वर्मा (2018) [7] ने अपने अध्ययन में पाया कि परिवार की आर्थिक स्थिति, अभिभावकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा घर में उपलब्ध अधिगम संसाधन बच्चों के शैक्षिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जिन बच्चों को उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण एवं सहयोग प्राप्त नहीं होता, उनमें सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी तथा उपलब्धि स्तर निम्न पाया जाता है।

शोध विधि: इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि (Survey Method) का उपयोग किया गया। सर्वेक्षण के माध्यम से चयनित ग्रामीण महिलाओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर तथा साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करके आवश्यक तथ्यों का संकलन किया गया तथा प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए।

जनसंख्या: इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज व परसपुर विकास खण्डों की ग्रामीण महिलाओं को जनसंख्या के रूप में शामिल किया गया है।

न्यादर्श: इस अध्ययन में गोंडा जिले के करनैलगंज व परसपुर विकास खण्डों के 5-5 गावों में निवास करने वाली 400 ग्रामीण महिलाओं को न्यादर्श के रूप में शामिल किया गया है । इस नमूने का चयन गैर-संभाव्यता उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण पद्धति के आधार पर किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य- प्रस्तुत शोध का निम्नवत उद्देश्य है
मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना- प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित परिकल्पना के अंतर्गत सम्पादित किया गया है-
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का उनकी प्रभावशीलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

विश्लेषण-
उद्देश्य- मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। परिकल्पना-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का उनकी प्रभावशीलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका 1: कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं प्रभावशीलता के मध्य संबंध

समस्याओं का स्तर	कार्यक्रम प्रभावी	प्रभावी नहीं	कुल
कम	150	30	180
मध्यम	80	40	120
अधिक	30	70	100
योग	260	140	400

$\chi^2=58.19$, df=2 तथा p-value=0.000

विश्लेषण-जिन क्षेत्रों में समस्याएँ कम थीं वहाँ कार्यक्रम अधिक प्रभावी पाए गए, जबकि अधिक समस्याओं वाले क्षेत्रों में प्रभावशीलता कम रही। $\chi^2 = 58.19$, $p<0.05$ प्राप्त हुआ।अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। निष्कर्षतः क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया।

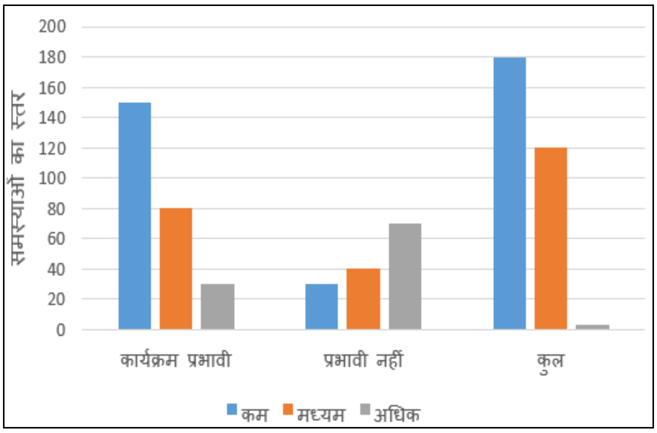

Fig 1: ग्राफ-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं प्रभावशीलता के मध्य संबंध

निष्कर्ष: मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण किया गया। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में कार्यक्रमों के संचालन के दौरान समस्याओं का स्तर कम था, वहाँ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। इसके विपरीत, जिन क्षेत्रों में समस्याओं का स्तर अधिक था, वहाँ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय कमी देखी गई। आँकड़ों के अनुसार, कम समस्याओं वाले समूह में 180 में से 150 (83.33%) उत्तरदाताओं ने कार्यक्रमों को प्रभावी माना, जबकि अधिक

समस्याओं वाले समूह में केवल 100 में से 30 (30.00%) उत्तरदाताओं ने कार्यक्रमों को प्रभावी बताया। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि क्रियान्वयन संबंधी बाधाएँ कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणामों को प्रभावित करती हैं तथा लाभार्थियों तक सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुँच में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

सांख्यिकीय परीक्षण में प्राप्त $\chi^2 = 58.19$ (df = 2, p = 0.000) यह सिद्ध करता है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं उनकी प्रभावशीलता के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संबंध विद्यमान है। चूँकि p-value 0.05 से कम है, इसलिए शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन के लिए क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं-जैसे संसाधनों की उपलब्धता, समय पर सेवाओं का वितरण, प्रशासनिक समन्वय तथा क्षेत्रीय निगरानी-का समाधान आवश्यक है। यदि इन बाधाओं को कम किया जाए तो मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। यह निष्कर्ष पूर्ववर्ती अध्ययनों के अनुरूप है, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता, संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता तथा प्रभावी निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं (Kothari, 2004; Ministry of Women and Child Development, 2021; UNICEF, 2019)।

शोध की उपयोगिता- प्रस्तुत शोध अध्ययन "मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन" अनेक दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम, जैसे— समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), जननी सुरक्षा योजना (JSY), पोषण अभियान, मिशन शक्ति तथा अन्य मातृ एवं बाल कल्याण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा छह वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण एवं परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराना है। किन्तु अनेक क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान प्रशासनिक कमियाँ, संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव, सेवाओं की अनियमित उपलब्धता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ़ियाँ, महिलाओं में जागरूकता की कमी, आर्थिक कठिनाइयाँ तथा भौगोलिक बाधाएँ जैसी समस्याएँ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। यह अध्ययन इन सभी समस्याओं एवं बाधाओं की पहचान कर उनके वास्तविक प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

इस अध्ययन की उपयोगिता नीति-निर्माताओं, प्रशासकों तथा कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में कौन-कौन से कारक प्रमुख बाधा बन रहे हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए किस प्रकार के सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। इससे योजनाओं के संचालन, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्राप्त होंगे।

यह अध्ययन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी केन्द्रों, आशा एवं एएनएम कार्यकर्ताओं तथा अन्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। अध्ययन के माध्यम से उन्हें यह जानकारी प्राप्त होगी कि लाभार्थियों तक सेवाएँ पहुँचाने में कौन-कौन सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण, समन्वय, जन-जागरूकता तथा सामुदायिक सहभागिता को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप सेवाओं की उपलब्धता, पहुँच एवं गुणवत्ता में सुधार संभव होगा।

ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं तथा बच्चों के दृष्टिकोण से भी यह अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। अध्ययन से यह ज्ञात होगा कि योजनाओं के प्रति जागरूकता, सामाजिक समर्थन, पारिवारिक निर्णय क्षमता, शिक्षा, आर्थिक स्थिति तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त करने को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके आधार पर महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने, नियमित प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच सुनिश्चित करने, पूर्ण टीकाकरण तथा संतुलित पोषण की उपलब्धता को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी रणनीतियाँ विकसित की जा सकेंगी।

शोध की दृष्टि से भी यह अध्ययन महत्वपूर्ण उपयोगिता रखता है। यह मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित उपलब्ध साहित्य में नवीन तथ्यों की वृद्धि करेगा तथा भविष्य के शोधकर्ताओं को अनुसंधान की नई दिशाएँ प्रदान करेगा। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग विभिन्न राज्यों, जनपदों अथवा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययनों में किया जा सकेगा। साथ ही यह शोध कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एक उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में भी कार्य करेगा।सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यह अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि स्वस्थ माताएँ ही स्वस्थ एवं सक्षम बच्चों का निर्माण करती हैं, जो किसी भी राष्ट्र के मानव संसाधन विकास की आधारशिला हैं। यदि अध्ययन के आधार पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यमान समस्याओं एवं बाधाओं का समाधान किया जाता है, तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा एनीमिया जैसी गंभीर समस्याओं में कमी लाई जा सकती है। इससे महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा जीवन-स्तर में सुधार होगा, जो अंततः सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति तथा समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस प्रकार यह अध्ययन केवल शैक्षणिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं नीति-निर्माण की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा।

सन्दर्भ

1. सेनगुप्ता वी. ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं को जागरूक करनाः एक समाजशास्त्रीय अनुशीलन (जिला: जाँजगीर-चाम्पा के नवागढ़ ब्लाक के संदर्भ में),शोध पत्र. Research Journal of Humanities and Social Sciences. 2012;3(3):342-346.
2. सुरवाडे, जितेंद्र बी. एवं सहलेखक: लातूर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के उपयोग का आकलन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 2013;3:25–30.
3. थनेश एस, उथायकुमार एस. वमराज्च्ची डिवीजन की शिक्षा स्थिति में सामाजिक-आर्थिक कारकों की भूमिका।, 2014.
4. सिंह आर. पी. स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य,अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।, 2018.
5. यादव आर. एस. महिला एवं बाल विकास: सिद्धांत, योजनाएँ एवं कार्यक्रम, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।, 2019.
6. अग्रवाल ए. एन. भारतीय सामाजिक समस्याएँ,न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।, 2019.
7. शर्मा एस. के. शोध एवं सांख्यिकी के मूल सिद्धांत,अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।, 2020.
8. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: जननी सुरक्षा योजना (JSY): संचालन दिशानिर्देश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2021.

9. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019–21): भारत तथ्य पत्रक,अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मुंबई।, 2021.
10. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: संचालन दिशा-निर्देश, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2021.
11. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): कार्यान्वयन रूपरेखा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2022.
12. विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2022, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा।, 2022.
13. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: पोषण अभियान: परिचालन दिशानिर्देश, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2023.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.